



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125207

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17194/2026

सुखेन गुप्ताआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	विपक्षी	(गण)
-------	--------	-------	--------------	------

आवेदक के अधिवक्ता : ज्ञान सागर, विद्या सागर द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विद्या सागर द्विवेदी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 42/2025, अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में आवेदक को जमानत पर रखा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं यह कहा गया है कि मृतक ने कुछ सामान उधार लिया था और आवेदक द्वारा धनराशि वापस मांगने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। यह आगे तर्क दिया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक 26.03.2026 से जेल में बंद है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।
- इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मृतक ने आवेदक से कुछ सामान उधार लिया था और जब आवेदक ने उससे धनराशि वापस मांगी, तो मृतक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका और विसरा सुरक्षित रखा गया था। यह आगे तर्क दिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक 26.03.2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखने के साथ-साथ एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय के अधिदेश और साथ ही जमानत देने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- सुखेन गुप्ता को संबंधित न्यायालय को संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।
 - (ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे निष्ठापूर्वक विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
 - (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।
11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 31.01.2023 को निर्णीत तथा (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट की गई 'जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ में : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021' के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रीजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

आर.के.एम.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"